RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 30 DECEMBER 2020 TO 05 JANUARY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 19 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर मिलेगी बैटरी अदला-बदली की सुविधा, वोल्टअप से हाथ मिलाया

Page 2

ऊषा ने किया किचन अप्लायंसेस और फैब्रिक केयर श्रृंखला का विस्तार

Page 4

भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में 'सबसे अधिक लचीली' साबित हो सकती है: संयुक्त राष्ट्र

Page 7

editoria!

मुद्रास्फीति की चुनौती

इस वर्ष महामारी और मंदी के संकट के साथ महंगाई की समस्या भी बड़ी गंभीर रही. अब अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखने लगे हैं, लेकिन मुद्रास्फीति में कमी के आसार नहीं हैं. उपभोक्ता मुद्रास्फीति की दर लगातार छह फीसदी से अधिक होने का मतलब यह है कि लोगों की जेब पर भार बढ़ रहा है. दर का यह स्तर रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य से बहुत अधिक है. कई जानकारों का मानना है कि अगले साल आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ाने से अधिक बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की हो सकती है. कुछ विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि बाजार में नगदी की बड़ी मात्रा को कम करने के लिए रिजर्व बैंक को जल्दी कदम उठाना चाहिए. संतोष की बात है कि महामारी नियंत्रित होती प्रतीत हो रही है तथा उत्पादन, मांग और रोजगार में सकारात्मक संकेत हैं. लेकिन इस वर्ष अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर ऋणात्मक रहने तथा उसे समुचित स्तर पर पहुंचने में कुछ समय लगने के कारण राष्ट्रीय आय के साथ लोगों की आमदनी में भी कमी बनी रहेगी. ऐसे में महंगाई का बरकरार रहना परेशानी की वजह बन सकता है. हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और निम्न आय वर्ग से है. रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में मामूली बढ़त भी उनके बजट पर असर डाल सकती है. कोरोना संकट से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे अधिक असर पड़ा है. मुद्रास्फीति अगर काबू में नहीं आयी, तो ये सेवाएं महंगी होती जायेंगी. आर्थिकी के गति पकड़ने के साथ रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, पर बेरोजगारी दर के अधिक होने से ये अवसर निकट भविष्य में पर्याप्त नहीं होंगे. बेरोजगारी में और आमदनी घटने की हालत में महंगाई की मार असहनीय हो सकती है. फसलों की आमद से अनाज, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों आदि की कीमतें घट सकती हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं के बारे में ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है. सरकारी कल्याण योजनाओं और राहत कार्यक्रमों से लोगों को एक हद तक मदद मिल रही है. आगामी बजट से भी लोगों को बड़ी आशाएं हैं. लेकिन एक आशंका यह भी है कि मुद्रास्फीति कम करने की कोशिश में अगर बाजार से नगदी की मौजूदा बड़ी मात्रा को कम किया गया, तो आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि नगदी कम होने से मांग पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. उम्मीद है कि सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रास्फीति की चुनौती से निपटने के लिए शीघ्र ही निर्णायक कदम उठाये जायेंगे. फिलहाल यह कोशिश होनी चाहिए कि कायदे-कानूनों का उल्लंघन कर महंगाई बढ़ाने और मुनाफा कमाने पर रोक लगे. जरूरी चीजों के दाम वाजिब होने चाहिए. यह चुनौती इसलिए गंभीर है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था भी उथल-पुथल से गुजर रही है और दूसरी तरफ मुद्रास्फीति की दर भी अधिक है. स्थिति ठीक होने में समय अधिक लग सकता है.

देश में फैलने लगा कोरोना का नया स्ट्रेन

UK की उड़ानों पर 7 जनवरी तक बढ़ा बैन

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस से बेहद संक्रामक नए स्ट्रेन ने भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया है। इस नए स्ट्रेन से बुधवार को 13 और लोग संक्रमित पाए गए। जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटेन जाने और आने वाली फ्लाइट्स पर 7 जनवरी 2021 तक बैन बढ़ा दिया है। पहले यूके की फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक बैन था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'ब्रिटेन में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानें अस्थायी रूप से 7 जनवरी 2021 रात 11:59 बजे तक निलंबित रहेंगी। ये निलंबन 22 दिसंबर को रात 11.59 बजे शुरू हुआ था। ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक का फैसला इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जनरल डायरेक्टर, नीति आयोग के अध्यक्ष, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (ऽउप्ए) और नेशनल टास्क फोर्स की संयुक्त निगरानी समूह (JMG) की सिफारिश पर लिया गया।

7 जनवरी के बाद सीमित उड़ानों की मिल सकती है मंजूरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह भी सुझाव दिया गया है कि 7 जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन से सीमित संख्या में उड़ानों को इजाजत दी जाए, लेकिन इन पर सख्ती से नजर रखी जाए। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझावों के बाद ही ये किया जाएगा। ब्रिटेन की फ्लाइट को लेकर अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्रिटेन से लौटे लोगों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है, जो संभावित 'सुपर स्प्रेडर' हो सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने इसके साथ ही नए साल के जश्न में भीड़ जमा नहीं होने देने की अपील भी की है। वहीं गृह मंत्रालय ने अपने हालिया आदेश में सभी राज्यों से कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीजों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें अनिवार्य रूप से क्वॉरंटीन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने यह भी निर्धारित किया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय स्थिति का तुरंत आकलन करें और 30 जनवरी और 31 दिसंबर, 2020 के साथ-साथ 15 जनवरी, 2021 को उचित प्रतिबंध लगाने पर विचार करें।

भारत में नए स्ट्रेन वाले 20 मरीजों की हुई पुष्टि

यूनाइटेड किंगडम से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इससे पहले बीते दिन भी देश के अलग-अलग हिस्सों से 6 ऐसे ही मामले सामने आए थे. कोलकाता में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का मामला आया है. यूके से लौटे एक व्यक्ति में स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं, जिसे अब क्वारनटीन कर दिया गया है। जीनोम स्क्रिवेंसिंग के बाद स्ट्रेन का पता लगा, शख्स पिछले हफ्ते ही यूके से वापस आया था। (शेष पेज 4 पर)

सरकार बिटक्वाइन ट्रेडिंग पर लगा सकती है 18 फीसदी जीएसटी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार बिटक्वाइन ट्रेडिंग पर 18 फीसदी गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रही है। बिटक्वाइन कारोबार करीब सालाना 40 हजार करोड़ रुपये आंका गया है। वित्त मंत्रालय की शाखा केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के समक्ष रखा है। सरकार को बिटक्वाइन की ट्रेडिंग से सालाना 7,200 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी (CryptoCurrency) बिटकॉइन (Bitcoin) में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है। मोटे मुनाफे के कारण बड़े निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं। गुरुवार को

पहली बार बिटक्वाइन 23000 डॉलर के पार पहुंच गया। इस साल बिटक्वाइन में 220 फीसदी की तेजी आ चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुरुवार को बिटक्वाइन की कीमतों में 9 फीसदी की तेजी आई और कीमत 23,256 डॉलर पहुंच गई। बिटक्वाइन और ब्लूमबर्ग गैलेक्स क्रिप्टो इंडेक्स इस साल तीन गुना हो चुके हैं। बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है। क्रिप्टोकरेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है।

ऐसे होती है बिटक्वाइन में ट्रेडिंग

बिटकॉइन ट्रेडिंग डिजिटल वॉलेट (Digital wallet) के जरिए होती है। बिटकॉइन की कीमत दुनियाभर में एक समय पर समान रहती है। इसे कोई देश निर्धारित नहीं करता बल्कि डिजिटली कंट्रोल होने वाली करंसी है। बिटकॉइन ट्रेडिंग का कोई निर्धारित समय नहीं है जिसके कारण इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव भी तेजी से होता है।

एल एंड टी ने भारत में बनायी थ्री डी निर्माण प्रौद्योगिकी पर आधारित इमारत

नयी दिल्ली। एजेंसी

लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने थ्री डी निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इमारत का सफलता पूर्वक निर्माण किया है। कंपनी का दावा है कि भारत में इस प्रौद्योगिकी के जरिये बनायी गयी यह पहली इमारत है। कंपनी ने तमिलनाडु स्थित अपने कांचीपुरम संयंत्र में थ्री डी निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर 700 वर्ग फुट 'बिल्ट अप एरिया' में इमारत तैयार की है। इसे सामान्य रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का उपयोग कर बनाये गये कंक्रीट से तैयार किया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, "21 अरब डॉलर की प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और निर्माण समूह एल एंड टी की निर्माण इकाई एल एंड टी कंस्ट्रक्शन ने थ्री डी निर्माण प्रौद्योगिकी से इमारत (ग्राउंड प्लस वन) तैयार की है। यह पहली बार है जब भारत में इस तरीके से कोई इमारत बनायी गयी है।" बयान के अनुसार देश 2022 तक सभी के लिये आवास काय्रक्रम के तहत 6 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, ऐसे में इस उपलब्धि से मकान बनाने में तेजी आएगी। एल एंड टी के पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (बिल्डिंग) एम वी सतीश ने कहा, "थ्री डी कंक्रीट प्रिंटिंग एक आधुनिक प्रौद्योगिकी है जो निर्माण की मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे निर्माण के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है...।" उन्होंने कहा कि इससे न केवल निर्माण कार्यों में तेजी आएगी बल्कि निर्माण गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन नवंबर महीने में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 92 लाख टन रहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन नवंबर महीने में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 92.45 लाख टन रहा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार पिछले साल 2019 के इसी माह में कच्चे इस्पात का उत्पादन 89.33 लाख टन रहा था। एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के अनुसार, "वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को रिपोर्ट देने वाले 64 देशों में कच्चे इस्पात का उत्पादन नवंबर 2020 में 15.826 करोड़ टन रहा। यह नवंबर 2019 के 14.842 करोड़ टन के मुकाबले 6.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ल्डस्टील ने कहा, "कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा कठिनाइयों को देखते हुए इस माह के आंकड़े को अगले महीने के उत्पादन अनुमान के साथ संशोधन किये जाने की संभावना है।" एसोसिएशन के आकड़े के अनुसार चीन का इस्पात उत्पादन नवंबर 2020 में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 8.766 करोड़ टन रहा। पिछले साल इसी महीने में यह 8.119 करोड़ टन था। अमेरिका का उत्पादन आलोच्य महीने में 61.20 लाख लाख टन रहा जो 2019 के नवंबर महीने में 70.88 लाख टन के मुकाबले 13.7 प्रतिशत कम है। जापान का उत्पादन चालू वर्ष में नवंबर महीने के दौरान 5.9 प्रतिशत घटकर 72.64 लाख टन रहा जो एक साल पहले 2019 के इसी महीने में 77.16 लाख टन था। दक्षिण कोरिया का इस्पात उत्पादन आलोच्य महीने में 2.4 प्रतिशत घटकर 57.6 लाख टन रहा जो एक साल पहले 2019 के नवंबर महीने में 59.04 लाख टन था। जर्मनी में कच्चे इस्पात का उत्पादन इस साल नवंबर महीने में 14.8 प्रतिशत बढ़कर 33.76 लाख टन रहा जो एक साल पहले इसी माह में 29.41 लाख टन था। ब्रसेल्स के वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन इस्पात उत्पादकों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संगठनों और इस्पात अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्य वैश्विक इस्पात उत्पादन का करीब 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हाजिर मांग के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मजबूत हाजिर मांग की वजह से कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा बाजार में कच्चा तेल की कीमत बुधवार को 26 रुपये की तेजी के साथ 3,553 रुपये प्रति बैरल हो गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जनवरी 2021 महीने में डिलिवरी वाले कच्चा तेल अनुबंध की कीमत 26 रुपये यानी 0.74 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,553 रुपये प्रति बैरल हो गयी। इसमें 1,420 लॉट के लिये कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से वायदा कारोबार में कच्चातेल कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव 0.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.30 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 51.35 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर था।

एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर मिलेगी बैटरी अदला-बदली की सुविधा, वोल्टअप से हाथ मिलाया

नयी दिल्ली। एजेंसी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के बाद अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) अपने चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी अदला-बदली की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत वह कुछ ही मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के स्थान पर पूरी तरह से चार्ज बैटरी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एचपीसीएल ने वोल्टअप के साथ करार किया है। वोल्टअप एक स्थान पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी अदला-बदली सुविधा प्रदान करने वाली स्टार्टअप है। वोल्टअप ने बयान में कहा कि इस भागीदारी के तहत जयपुर में दो बैटरी अदला-बदली स्टेशन शुरू किए गए हैं। इस भागीदारी के तहत अगले छह माह में देशभर में 50 बैटरी अदला-बदली समाधान केंद्र खोले जाएंगे। चार्जिंग ढांचे की कमी, ऊंची लागत और चार्जिंग में लगने वाले लंबे समय की वजह से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते में अड़चनें आ रही हैं। बयान में कहा गया है कि इस कमी को दूर करने के लिए वोल्टअप और एचपीसीएल ने हाथ मिलाया है। इस भागीदारी के तहत देशभर में एचपीसीएल के नेटवर्क और वोल्टअप की बैटरी अदला-बदली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। इससे पहले आईओसी ने अपने पेट्रोल पंपों पर बैटरी अदला-बदली सुविधा के लिए सन मोबिलिटी के साथ भागीदारी की थी।

विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़कर 581.131 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 2.563 अरब डॉलर बढ़कर 581.131 अरब डालर की नयी रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 77.8 करोड़ डॉलर घटकर 578.568 अरब डॉलर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में बढ़ोतरी आने के कारण मुद्रा भंडार में तेजी दर्ज की गई। विदेशीमुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षावधि में एफसीए 1.382 अरब डॉलर बढ़कर 537.727 अरब डॉलर हो गयीं। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है। आंकड़ों के अनुसार 18 दिसंबर को समाप्त सप्ताह हुए समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान देश का स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.008 अरब डॉलर बढ़कर 37.020 अरब डॉलर हो गया। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार 1.2 करोड़ डॉलर की बढ़त के साथ 1.515 अरब डॉलर और आईएमएफ के पास जमा मुद्रा भंडार भी 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.870 अरब डॉलर हो गया।

उच्चतम स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार, 47750 के करीब बंद हुआ

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसई निफ्टी दोनों नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुए। वित्तीय कंपनियों, वाहन और आईटी कंपनियों के शेयरों की अगुवाई में शेयर बाजारों में यह तेजी आयी है। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 133.14 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 47,746.22 अंक की रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह एक समय अब तक के सर्वोच्च स्तर 47,807.85 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49.35 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ रिकार्ड 13,981.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 13,997 के उच्चतम स्तर तक चला गया था। सेंसेक्स के शेयरों में अल्ट्राटेक में 4 प्रतिशत से अधिक की मजबूती आयी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में 2.63 प्रतिशत और मारुति में 2 प्रतिशत की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचयूएल, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स भी बढ़त में रहे। एस्ट्राजेनका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 टीके को ब्रिटेन में मंजूरी से यूरोपीय शेयर बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी रही। ब्रिटेन ने इसके साथ ही कोविड-19 के दूसरे टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जापान का तोक्यो और आस्ट्रेलिया में सिडनी बाजारों में गिरावट रही जबकि हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का कंपोजिट सूचकांक में तेजी आयी। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले पांच कारोबारी सत्रों में तेजी के बाद बुधवार को बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में मुनाफा वसूली के चलते गिरावट हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.10 फीसदी की बढ़त के साथ खुला लेकिन यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी और सूचकांक 102.99 अंक या 0.22 प्रतिशत घटकर 47,510.09 अंक पर आ गया। 27.45 अंक या 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,905.15 पर था। निफ्टी 10.75 अंक बढ़कर 13,943.35 पर खुला था।

जनवरी से महंगा हो सकता है टीवी, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान, कीमतों में 10 प्रतिशत वृद्धि संभव

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नए साल में यानी जनवरी से एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन जैसे अन्य टिकाऊ घरेलू सामान की कीमतें 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात जैसे कच्चे माल की लागत बढ़ने और परिवहन भाड़ा महंगा होने के कारण कीमतों में वृद्धि संभव है. विनिर्माताओं ने कहा कि इसके अलावा आपूर्ति में कमी के कारण टीवी पैनल (ओपेन सेल) की कीमतें भी दोगुनी से अधिक हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही प्लास्टिक भी महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि एलजी, पैनासोनिक और थॉमसन जैसे विनिर्माताओं के लिए जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जबकि सोनी अभी भी हालात की समीक्षा कर रही है और उसे इस बारे में निर्णय करना है।

पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ मनीष शर्मा ने कहा, 'हमारा मानना है कि निकट भविष्य में जिंस कीमतों में बढ़ोतरी से हमारे उत्पादों की कीमतें प्रभावित होंगी। मेरा अनुमान है कि जनवरी में 6-7 प्रतिशत कीमतें बढ़ेंगी और वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक ये 10-11 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।'

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भी अगले साल एक जनवरी से कीमतों में सात से आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के उपाध्यक्ष (घरेलू उपकरण) विजय बाबू ने कहा, 'जनवरी से हम टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि सभी उत्पादों की कीमतों में सात से आठ प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कच्चे माल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लास्टिक सामग्री की लागत भी काफी हद तक बढ़ गई है।'

सोनी इंडिया कीमतों में बढ़ोतरी पर स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसने इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है। इस बारे में पूछने पर सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नय्यर ने कहा, 'फिलहाल नहीं। अभी इंतजार किया जा रहा है। हम आपूर्ति पक्ष को देख रहे हैं, जो दिन-प्रतिदिन बदल रहा है। हालात, अस्पष्ट हैं और हमने इस बारे में अभी तय नहीं किया है।'' उन्होंने कहा कि पैनल की कीमतें और कुछ कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, खासतौर से टीवी के लिए।

कारोबारियों की जीएसटी परिषद से नई जीएसटी अधिसूचना को संशोधित करने की मांग

कोलकाता। एजेंसी

व्यापारी समुदाय ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद से हाल में जारी की गई नई जीएसटी अधिसूचना के कुछ प्रावधानों को वापस लेने का आग्रह किया। सरकार ने 22 दिसंबर को जीएसटी नियमों के कुछ प्रावधानों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की थी और कुछ नियम अगले साल एक जनवरी से लागू होने वाले हैं। एक बिंदु पर ही जीएसटी संग्रह की वकालत कर रहे छोटे व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापर मंडल ने एक ज्ञापन के जरिए हाल में जारी की गई जीएसटी अधिसूचना में कुछ बदलाव करने का आग्रह किया। संगठन के महासचिव वी के बंसल ने कहा, ''एक जनवरी 2021 से प्रभावी होने वाले नियम 86बी और 36(4), को रद्द कीजिए। ये प्रावधान जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ हैं, क्योंकि ये सहज रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट को बाधित करते हैं।'' केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक जनवरी 2021 से लागू होने वाले जीएसटी नियमों के तहत नियम 86-बी को संशोधित किया है, जिसके तहत जीएसटी देयता को 99 फीसदी तक पहुंचाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसका अर्थ है कि 50 लाख से अधिक मासिक कारोबार वाले कारोबारियों को अपने जीएसटी दायित्व का कम से कम एक प्रतिशत अनिवार्य रूप से नकद भुगतान करना होगा।

दूरसंचार उद्योग पर वित्तीय दबाव बरकरार, सीओएआई ने सरकार से मांगा समर्थन

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के दौरान दूरसंचार उद्योग द्वारा उपलब्ध सुविधा के चलते डिजिटल का उपयोग काफी बढ़ा है, लेकिन उद्योग खुद वित्तीय संकट में घिरा हुआ है। दूरसंचार ऑपरेटरों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने नकदी संकट, शुल्कों को सुसंगत बनाने, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) और स्पेक्ट्रम के मूल्य जैसे मुद्दों पर सरकार से उद्योग को समर्थन की मांग की है। सीओएआई ने अपने 2021 के परिदृश्य में कहा कि पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा-5जी के 2021 में शुरू होने की उम्मीद है। सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने सोमवार को बयान में कहा कि प्रौद्योगिकी की वजह से कई तरह की संभावनाएं खुलेंगी। कारोबारी मॉडल से लेकर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा, 'उद्योग पर वित्तीय दबाव कायम है। हम सरकार का समर्थन चाहते हैं जिससे उद्योग चौतरफा आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके।'' उन्होंने कहा कि तरलता की समस्या को दूर करना, नियामकीय शुल्कों को तर्कसंगत करना, एजीआर के मुद्दे, स्पेक्ट्रम मूल्य, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियम और मोबाइल टावरों से विकिरण की समस्या जैसी उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। कोचर ने कहा कि सीओएआई सरकार और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के समक्ष लगातार ये मुद्दे उठा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह दूरसंचार भी महामारी से प्रभावित हुआ और मार्च तथा अप्रैल में उद्योग के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। हालांकि, बाद में कारोबार जगत और व्यक्तिगत लोगों द्वारा डिजिटल के इस्तेमाल से उद्योग का 'बचाव' हो सका। उन्होंने कहा कि डेटा ट्रैफिक में भारी इजाफे से कई दूरसंचार कंपनियों को काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि दूरसंचार क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों से बेहतर रहा है।

एक जनवरी से ईवे बिल की वैधता अवधि घटाने के विरोध में हैं ट्रांसपोर्टर्स

नयी दिल्ली। एजेंसी

ट्रांसपोर्टर्स की शीर्ष संस्था एआईएमटीसी ने मंगलवार को कहा कि वह एक जनवरी से ई-वे बिल की वैधता अवधि को कम करने के खिलाफ है। संगठन ने कहा कि इस कदम से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी और अफरा-तफरी की स्थिति पैदा होगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ट्रांसपोर्टर्स की संस्था है, जो लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एआईएमटीसी ने एक बयान में कहा, ''इस क्षेत्र ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया है और ऐसे में सरकार एक अधिसूचना जारी कर अव्यावहारिक परिस्थिति बना रही है। इस अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने ई-वे बिल की वैधता अवधि आधी कर दी है।'' संगठन ने कहा कि सरकार की उक्त अधिसूचना अच्छे से तैयार नहीं की गयी है। सरकार ने संबंधित पक्षों के साथ बिना कोई बातचीत किये ही यह अधिसूचना जारी कर दी है। उसने कहा कि इस संशोधन से आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू प्रवाह में बाधा आ सकती है और दवाएं व जल्द खराब होने वाली वस्तुओं सहित आवश्यक आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।

बार एग्जाम हेतु इंदौर परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर बीसीआई को धन्यवाद ज्ञापित

लगभग 1000 स्टूडेंट्स को जाना होता था भोपाल या जबलपुर

इंदौर। कानूनी और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था न्यायाश्रय द्वारा सनद की परीक्षा के लिए इंदौर को परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग विगत 3 वर्षों से निरंतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को की गई थी जो अब जाकर मंजूर हो गई है। एलएलबी और बीएएलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के उपरांत वकालत करने हेतु लाइसेंस (सनद) के लिए होने वाली परीक्षा इंदौर को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने से सैकड़ों छात्र छात्राओं को भोपाल अथवा जबलपुर परीक्षा देने जाना पड़ रहा था। इंदौर से प्रतिवर्ष लगभग 1000 छात्र-छात्राएं बार एग्जाम के लिए इंदौर को परीक्षा केंद्र ना घोषित किए जाने पर परेशान होते थे जिसको लेकर इंदौर के अधिवक्ता एवं विधि व्याख्याता पंकज वाधवानी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग की थी कि इंदौर को भी बार एग्जाम का परीक्षा केंद्र घोषित किया जाए। इस वर्ष से बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इंदौर को परीक्षा केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जिससे कानून के विद्यार्थियों को राहत मिली है। संस्था न्यायाश्रय के अध्यक्ष पंकज वाधवानी द्वारा इंदौर को परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग को लेकर यह तर्क दिया था कि जिन शहरों को बार एग्जाम का परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है उससे अधिक छात्र तो इंदौर से हैं ऐसे में इंदौर को परीक्षा केंद्र बनाया जाना पूर्णतया उचित है ।

क्या है बार एग्जाम

अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने जानकारी दी कि प्रोफेशनल स्किल्स एवं वकालत के मानकों में हो रही गिरावट को लेकर कुछ वर्ष पूर्व वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एल एलबी एवं बीएएलएलबी उत्तीर्ण करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा पूरे किए गए पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पत्र उत्तर करना आवश्यक होता है। उक्त प्रश्न पत्र सौ वैकल्पिक प्रश्नों का होता है जिसमें से न्यूनतम 40 अंक लाना आवश्यक है। बार एग्जाम आयोजित करने का उद्देश स्टूडेंट की वकालत स्किल एवं न्यूनतम जानकारी को परखना है।

2021 में सुधारों की अगुवाई करेंगी श्रम संहिताएं रोजगार के अवसर तैयार करने की बड़ी चुनौती

नई दिल्ली। एजेंसी

अगले साल एक अप्रैल से चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से औद्योगिक संबंधों में सुधार की दिशा में एक नई शुरुआत होगी, जिससे अधिक निवेश जुटाने में मदद मिलेगी, हालांकि रोजगार सृजन का मुद्दा 2021 में भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहेगा। कोविड-19 महामारी के चलते ये साल कार्यबल के साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है। सरकार ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया, जिसका आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा और इसके चलते बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों को अपने मूल स्थान की ओर पलायन करना पड़ा। कई प्रवासी मजदूरों ने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें अपने मूल स्थानों से काम पर वापस लौटने में महीनों लग गए।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की शोध शाखा के प्रमुख और पूर्व महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा कि भारत को बड़ी संख्या में श्रमिकों की नौकरी बहाल करने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने महामारी के कारण अपनी आजीविका खो दी। उन्होंने आगे कहा कि नई नौकरियां सृजित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में गिरावट, ऑटोमेशन और 'वर्क फ्रॉम होम जैसी नई अवधारणाओं से कई चुनौतियां पैदा हुई हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार 2020 में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिए जो कर सकती थी, उसने किया। उपाध्याय ने कहा कि महामारी के प्रभाव को देखते हुए अब नीति निर्माताओं को 2021 में लागू किए जाने वाली नई श्रम संहिताओं में जरूरी सुधार के बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में समग्र खपत तब तक नहीं सुधरेगी, जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं होगा और केवल उत्पादन को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से पहले के स्तर पर लौटने में मदद नहीं मिलेगी।

केंद्र सरकार हालांकि महामारी के बीच तीन श्रम संहिताओं के लिए संसद की मंजूरी पाने में सफल रही। इसके अलावा मजदूरी संहिता को पिछले साल संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। सरकार ने इस साल हितधारकों की प्रतिक्रिया पाने के लिए तीन संहिताओं के मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है और इस पर सुझाव देने की समय सीमा जनवरी के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 दिसंबर को वेतन और औद्योगिक संबंधों के नियमों पर विचार-विमर्श के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी। अगली त्रिपक्षीय बैठक 12 जनवरी को सामाजिक सुरक्षा और ओएसएच पर संहिता पर विचार-विमर्श के लिए निर्धारित है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने ने कहा कि हम एक अप्रैल 2021 से चारों श्रम संहिताओं को लागू करना चाहते हैं। औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और ओएसएच संहिता पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की समयसीमा जनवरी में खत्म हो जाएगी।

चंद्रा ने कहा कि इन चार संहिताओं के लागू कर सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ ही श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि मेरी कामना है कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही नव वर्ष 2021 देश में विकास के एक नए युग की शुरूआत करेगा और यह मजदूरी सुरक्षा, काम करने का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे 50 करोड़ कर्मचारियों के साथ ही उद्योग जगत के लिए यह वर्ष समृद्धि और विकास का होगा। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं का मकसद वर्तमान श्रम कानूनों के जटिल ढांचे को सरल बनाकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और साथ ही श्रमिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है।

ऊषा ने किया किचन अप्लायंसेस और फैब्रिक केयर श्रृंखला का विस्तार

अत्याधुनिक मिक्सर ग्राइंडर्स और स्टीम आयरन पेश किये

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे ज्यादा भरोसेमंद और प्रमुख कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ब्राण्ड्स में से एक, ऊषा इंटरनेशनल ने इस सीजन में 13 किचन और होम अप्लायंसेस की श्रृंखला पेश की है। यह उत्पानद उन उपभोक्ता ओं पर लक्षित हैं जो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठे ऐसे उत्पापद खरीदना चाहते हैं जोकि उन्हें सहूलियत देने के साथ ही उनके वर्क-फ्रॉम-होम के दौर और उसके बाद भी सहायता करने में सक्षम हों। यह सभी नई पेशकशें बहुत ही आकर्षक खरीदारी हैं। नए पेश किए गए उत्पीदों में किचन अप्लायंसेस कैटेगरी में 9 मिक्सर ग्राउंडर्स और फैब्रिक केयर कैटेगरी में स्टीम आयरंस की एक श्रृंखला शामिल है। मिक्सर ग्राइंडर्स में ट्राइएनर्जी प्लस मिक्सर ग्राइंडर, मैक्जिमस प्लस मिक्सर ग्राइंडर और पावर स्पिन मिक्सर ग्राइंडर, जबकि स्टीम आयरन में एक्वा ग्लो, ग्रैण्ड जेट, हेलिक्स प्रो और मिस्टेलो जैसे उत्पा द शामिल हैं। ऊषा लगातार ऐसे उत्पादों को विकसित करने का प्रयास करती

है, जो उपभोक्ताओं की जरूरतों और आधुनिक रहन-सहन के अनुसार हों। इन नई पेशकशों के बारे में श्री सौरभ बैसाखिया, प्रेसिडेन्ट-अप्लायंसेस, ऊषा इंटरनेशनल, ने कहा, "अनलॉक की शुरूआत के साथ ही हमारी बिक्री का बढ़ना यह साबित करता है कि उपभोक्ताओं ने हम पर विश्वास किया है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उत्पादों और अनुभवों की पेशकश करते हैं। हमने अनलॉक के बाद वाले महीनों में बढ़ी हुई मांग को पूरा किया, जिससे बिक्री का बढ़ना जारी रहा और हमें आशा है कि हमारी नई पेशकश बिक्री को और बढ़ाएंगे, क्योंकि वे बहु-कार्यात्मकता और मूल्य के प्रस्ताव के लिहाज से बेहद आकर्षक हैं। हम उपभोक्ताब के अनुभव को भी बेहतर बनाने पर ध्यारन दे रहे हैं फिर चाहे वह ऑनलाइन हो या इन-स्टोर। साथ ही हम उन्हेंभ बिक्री पश्चात शानदार सेवा प्रदान करेंगे और उपभोक्ताओं के डिजिटल जुड़ाव को और अच्छाइ बनाएंगे ताकि वे घर बैठे सुरक्षित ढंग से उत्पाद प्राप्त कर सकें। हम काउंटर/बाजार हिस्से दारी बढ़ाने के लिए भौगोलिक एवं संख्या की दृष्टि से विस्तार करेंगे।"

कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दे दी है। मिसाइल के निर्यात को तेजी से मंजूरी देने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्यात किया जाने वाला मिसाइल सिस्टम वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संस्करण से अलग होगा। बता दें कि आकाश मिसाइल सिस्टम 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण के साथ देश की महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (ॐऊ) द्वारा विकसित किया गया है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डालर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस कदम को उठाया है।

देश में फैलने लगा कोरोना का नया स्ट्रेन

(पेज 1 का शेष)

अब तक ब्रिटेन से लौटे 1423 लोगों की हुई ट्रेसिंग

सरकार ने एक बयान में बताया कि अब तक ब्रिटेन से लौटे 1423 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। 17 लोगों की तलाश की जा रही है। ब्रिटेन से लौटे 1406 लोगों का टेस्ट किया गया, इनमें 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन सभी के संपर्क में आए 6364 लोगों में से भी 12 संक्रमित हुए हैं. सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हैदराबाद भेजे गए हैं।

ब्रिटेन में कोरोना के दो नए वैरिएंट मिले

ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस के ज्यादा खतरनाक दो वैरिएंट मिल चुके हैं। पहला वैरिएंट मिला इसके बाद ही भारत सरकार ने 21 दिसंबर को ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन के अलावा इस नए स्ट्रेन के केस भारत, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में सामने आ चुके हैं। उधर, दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है. यह ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से अलग है।

'स्वच्छता का पंच' लगाने के लिये वेस्ट से बेस्ट की क़वायद शुरु

इंदौर। मॉडर्न ग्रुप द्वारा बनाये गये 'बेस्ट आउट ऑफ़ वेस्ट' आर्ट वर्क का अनावरण श्री संदीप सोनी (Additional Commissioner & Nodal Officer- Swachh Bharat Abhiyan-Indore) जी ने किया। मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स इंदौर के अंतर्गत संचालित मॉडर्न इंटरनैशनल स्कूल द्वारा 3 इनिशियेटिव को दर्शाता कचरे का उपयोग कर एक अद्भुत आर्ट को बनाया गया है। जिसका उद्घाटन आज प्रातः 9:00 बजे मेघदूत गार्डेन के प्रवेश द्वार पर नोडल ऑफ़िसर स्वच्छ भारत-इंदौर श्री संदीप सोनी जी द्वारा किया गया। श्री सोनी ने मॉडर्न ग्रुप के इस इनिशियेटिव की प्रशंसा की। शहर के अन्य संस्थानों को ऐसे नवाचार में भाग के लेने के लिये श्री सोनी ने आग्रह किया। आज यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संस्था की प्रधानाचार्य श्री मती प्रदन्या कस्तूरे ने बताया कि संस्थाध्यक्ष श्री अनिल खरया जी का यह विजन है कि शहर के सुंदरीकरण हेतु वेस्ट मैटेरियल्स का उपयोग कर 3 आर के लक्ष्यों प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि यह क्रियेटिव आर्ट मॉडर्न ग्रुप के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। संस्था के समूह निदेशक डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी स्वच्छ भारत इंदौर के

ब्रांड एंबेसडर भी हैं। इस विमोचन कार्यक्रम में डॉ. द्विवेदी ने यह घोषणा की कि इस प्रकार के अन्य कई वेस्ट टू बेस्ट आर्ट वर्क शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा लगाया जायेगा। संस्थाध्यक्ष श्री अनिल खरया ने कहा कि अपोलो हस्पतील के पास के पार्क के सुंदरीकरण की ज़िम्मा मॉडर्न ग्रुप ले रही है और कल से ही सफ़ाई और सुंदरता का काम शुरु कर दिया जायेगा। श्री संदीप सोनी (नोडल ऑफ़िसर-स्वच्छ भारत अभियान इंदौर) ने श्री खरया के इस प्रस्ताव की स्वागत किया। कार्यक्रम में नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे साथ ही साथ मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स के उपाध्यक्ष श्री शांतनु खरया सबका स्वागत किया। संस्था की मीडिया प्रभारी अर्पिता पटेल ने यह जानकारी दी है।

ग्लेनमार्क भारत में पहली कंपनी

टाइप 2 डायबिटीज वाले की सस्ती कीमत पर रेमोग्लिफ्लोज़िन + विल्डाग्लिप्टिन का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन लॉन्च

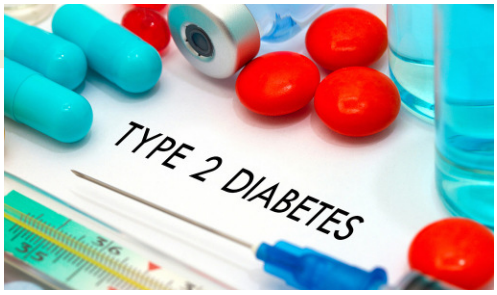

आईपीटी नेटवर्क

इंदौर। शोध-केंद्रित वैश्विक दवा कंपनी, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ग्लेनमार्क) ने भारत में अपने नवीनतम, पेटेंट-संरक्षित और विश्व स्तरीय शोध-आधारित सोडियम ग्लूकोज को-ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर (एस.जी. एल.टी.2ग) - रेमोग्लिफ्लोज़िन एटाबोनेट का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफ.डी.सी) तथा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य डीपीपी 4 इनहिबिटर (डाईपेप्टाइडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर) – विल्डाग्लिप्टिन लॉन्च किया। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन टाइप 2 डायबिटीज की देखभाल में मदद करता है। कॉम्बिनेशन के तहत एक फिक्स्ड डोज में रेमोग्लिफ्लोज़िन (100 मिलीग्राम) ₹ विल्डाग्लिप्टिन (50 मिलीग्राम) होगा और रोगियों में ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए इसे रोजाना दो बार लिया जाना चाहिए। ग्लेनमार्क ने इसे दो ब्रांड नाम रेमो ₹ और रेमोजेन ₹ के अंतर्गत लॉन्च किया है।

ग्लेनमार्क दुनिया की पहली कंपनी है जिसने रेमोग्लिफ्लोज़िन ₹ विल्डाग्लिप्टिन फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन लॉन्च किया है और भारत इस एफ.डी.सी दवा तक पहुँच पाने वाला पहला देश है। ग्लेनमार्क को नवंबर 2020 के अंतिम दिनों में रेमोग्लिफ्लोज़िन ₹ विल्डाग्लिप्टिन कॉम्बिनेशन की मैन्यूफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए डी.सी.जी.आई (भारत का दवा अनुमोदन प्राधिकरण) से मंजूरी मिली। विश्व स्तर पर, एसजीएलटी2, इनहिबिटर और डीपीपी4 इनहिबिटर, टाइप 2 डायबिटीज की देखभाल के पसंदीदा उपचार विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। भारत में डायबिटीज के रोगियों के लिए कम कीमत पर नवीनतम उपचारों तक पहुंच प्रदान करने में ग्लेनमार्क सबसे आगे रहा है। टाइप 2 डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियों में, रोगियों को लंबे समय तक कई डायबिटीज-रोधी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। इसके अलावा, भारत में, रोगियों को अपने दम पर दवा का खर्च उठाना पड़ता है और इसलिए दवा की कीमत उपचार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बन जाती है। जहां एक ही दवा श्रेणी में मौजूदा ब्रांड की औसत दैनिक थेरेपी लागत 78 रुपये है, वहीं ग्लेनमार्क के रेमोग्लिफ्लोज़िन ₹ विल्डाग्लिप्टिन कॉम्बिनेशन को 14 रुपये प्रति टैबलेट की कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिसे रोजाना दो बार लेना होता है, जिसकी लागत 28 रुपये प्रति दिन होती है। यह लागत बाजार में उपलब्ध अन्य एसजीएलटी2 और डीपीपी4 कॉम्बिनेशन दवाओं की तुलना में 65% कम है।

श्री आलोक मलिक, ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट एवं बिजनेस हेड, इंडिया फॉर्मुलेशंस ने कहा कि 'ग्लेनमार्क भारत में डायबिटीज रोगियों के लिए नवीनतम उपचार विकल्पों तक पहुंच प्रदान करने में अग्रणी रहा है। इस इनोवेटिव फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को पेश करते हुए हमें खुशी महसूस हो रही हैं। यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल आधुनिक है, इसके लिए बड़े पैमाने पर शोध किया गया है और यह देश में मरीजों के लिए किफायती कीमत पर उपलब्ध है। ग्लेनमार्क के लिए डायबिटीज महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस प्रॉडक्ट के लॉन्च से हम भारत में रोगियों को एक प्रभावी, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विश्व स्तरीय और किफायती उपचार विकल्प प्रदान करके डायबिटीज उपचार को बेहतर बना पाएंगे।'

'एआईसीटीपीएल' का मेडेन अमेरिकी डॉलर बॉन्ड और एपीएसईज़ेड की जेवी कंपनी का पहला बॉन्ड जारी

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

एआईसीटीपीएल ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना मेडेन पब्लिक बॉन्ड इश्यूएंस को 21 दिसम्बर 2020 को सेटल किया। इस इश्यू में बड़े रियल मनी इन्वेस्टर्स की भागीदारी दर्ज की गई, जिसमें लगभग 220 अकाउंट्स ने अपनी रुचि दिखाई और यह लगभग 10 गुना ओवरस्क्रिप्शन रहा। ।10 वर्षों के इश्यू का मूल्य 3.00ङ के सममूल्य पर रहा, जो पिछले 5 वर्षों में किसी भी कॉरपोरेट भारतीय इश्यूअर द्वारा हासिल किया गया न्यूनतम कूपन है। निवेशक इसके मजबूत शेयरधारकों, एपीएसईज़ेड और टीआईएल, और कंपनी में उनकी संयुक्त व्यापारिक मजबूती को देखते हुए आकर्षित हुए थे, जो सभी 3 अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की निवेश ग्रेड रेटिंग पुष्टि द्वारा समर्थित क्रेडिट गुणवत्ता द्वारा संचालित थे। यह इश्यूएंस अदाणी ग्रुप की सोच के अनुरूप है, जो परिसंपत्तियों के लिए पूंजी संरचना को फिर से इंजीनियर करने के लिए पूंजी बाजार को उपयोग करता है और प्रोजेक्ट के जीवन भर के लिए ऋण को विस्तारित करते हुए उनका वित्तपोषण करता है। इश्यूएंस पूरी तरह से टीआईएल की रणनीति के भी अनुरूप है, जो विश्व में अपनी टर्मिनल कंपनियों के लिए धन स्रोतों में विविधता लाने और अनुकूलन करने के लिए काम करता है। बार्कलेज, सिटीग्रुप, डीबीएस बैंक, एमयूएफजी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स, बुक-रनर्स और प्रमुख प्रबंधक रहे। एपीएसईज़ेड के सीईओ और होलटाइम डायरेक्टर श्री करण अदाणी ने कहा कि 'इश्यूएंस, पूंजी संरचना की री-इंजीनियरिंग करने और परिसंपत्ति के जीवन के लिए ऋण परिपक्वता इनलाइन का विस्तार करने के ग्रुप की पूंजी प्रबंधन सोच के अनुरूप है। टीआईएल के साथ हमारा संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुंद्रा कंटेनर हब को क्षेत्र और एआईसीटीपीएल का हमारा फ्लैगशिप टर्मिनल बनाने की हमारी रणनीति की कुंजी है। सफल इश्यूएंस, प्राइवेट जेवी स्तर पर कॉरपोरेट प्रशासन के स्तर की सराहना और स्वीकृति को दर्शाता है। किसी भी पोर्ट वर्टिकल जेवी कंपनी द्वारा पहला नोट इश्यूएंस, पूंजी बाजार का दोहन करने के लिए अन्य जेवी और ग्रुप की सहायक कंपनियों के लिए रास्ता बनाता है और बेंचमार्क निर्धारित करता है।'

adani
Ports and Logistics

'घर से काम' का कार्यालय स्थलों की मांग पर हुआ असर

2020 में 44 प्रतिशत घटी मांग: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश के सात प्रमुख शहरों में दफ्तर के लिये जगह पट्टे पर लेने में साल 2020 में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। यह घटकर 2.58 करोड़ वर्गफुट रह गयी। कोविड-19 महामारी के कारण कंपनियों ने अपनी विस्तार योजना फिलहाल टाल दी है और कर्मचारियों के लिए 'घर से काम (वर्क फ्रॉम होम)' की नीति अपना रहीं हैं। संपत्ति क्षेत्र की सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और बेंगलूरू इन सात शहरों में 2019 में कार्यालय के लिये 4.65 करोड़ वर्गफुट जगह ली गई। जेएलएल ने कहा कि हालांकि, 2020 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कार्यस्थल की मांग 52 प्रतिशत बढ़कर 82.7 लाख वर्गफुट रही जबकि इससे पिछली तिमाही में मांग 54.3 लाख वर्गफुट की रही। इस साल जनवरी जनवरी-मार्च के दौरान कार्यालय स्थल की कुल खपत 88 लाख वर्गफुट रही। यह खपत इस साल की दूसरी तिमाही में 33.2 लाख वर्गफुट रही थी। दूसरी तिमाही में मांग पर लॉकडाउन का असर रहा था। जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं कंट्री हेड रमेश नायर ने कहा, "साल 2019 में कुल खपत 4.6 करोड़ वर्गफुट से ऊपर ऐतिहासिक स्तर पर रही थी। इससे तुलना की जाये तो 2020 में खपत में 44 प्रतिशत की गिरावट आयी। हालांकि 2016 से 2018 के दौरान की औसत शुद्ध खपत के स्तरों की तुलना करें तो भारतीय कार्यालय बाजार की लचीली प्रकृति का सही अंदाजा लगता है।"

निर्यात सब्सिडी, एथेनॉल मूल्य वृद्धि से चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन सुधरेगा: रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सरकार द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के लिए घोषित 3,500 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी, स्थिर घरेलू मांग और एथनॉल की कीमत वृद्धि के कारण चीनी मिलों का परिचालन लाभ 10.5 - 11.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। क्रिसिल रेटिंग ने एक रिपोर्ट में कहा कि चीनी सत्र 2021 के अक्टूबर-सितंबर के लिए सरकार द्वारा घोषित निर्यात सब्सिडी, चीनी निर्यात को लगभग पिछले साल के स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा। इसके साथ, घरेलू मांग पूर्वस्तर पर बने रहने, एथनॉल उत्पादन में गन्ने के अधिक उपयोग से एथेनॉल से अधिक प्राप्ति तथा एथनाल के दाम बढ़ने से चीनी मिलों के परिचालन मार्जिन में एक से दो प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो बढ़कर चालू वित्तवर्ष में 10.5-11.5 प्रतिशत तक हो जायेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने हाल ही में चीनी सत्र 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिये 3,500 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी (करीब 5.8 रुपये प्रति किलो) को मंजूरी दी है। क्रिसिल रेटिंग के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, "हालांकि, चीनी सत्र 20 के लिए घोषित 10.4 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी से मौजूदा कम सब्सिडी, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए घरेलू चीनी मिलों को उत्पादन लागत की वसूली करने में मदद मिलेगी जिसके कारण निर्यात लाभप्रद होगा।" क्रिसिल का मानना है कि निर्यात के लिए कम विकल्प उपलब्ध होने के कारण चालू चीनी सत्र में निर्यात की मात्रा 50-55 लाख टन रह सकती है जो 60 लाख टन के लक्ष्य से थोड़ा कम है। इस बीच, उच्च औद्योगिक मांग के कारण चीनी सत्र 2021 में घरेलू खपत पिछले साल के 2.55-2.6 करोड़ टन के स्तर पर पूर्ववत बने रहने की संभावना है, जो कुल मांग का 60 प्रतिशत है। होटल, रेस्तरां और कैफे से मांग उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के संबंध में सावधानी बरतने के कारण सुस्त बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों द्वारा खरीदे गए एथेनॉल की कीमत हाल ही में 4.4 -6.2 प्रतिशत बढ़ाई गई थी ताकि ईंधन सम्मिश्रण करने के लिए एथेनॉल की आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।

कैसा होगा नया साल आपके लिए

हम जानते हैं, पूरे विश्व के लिए वर्ष 2020 काफी मुश्किलों और चुनौतियों से भरा रहा। न या साल 2021 कैसा होगा? वास्तव में नया साल नई उम्मीदों के साथ नई तरह की चुनौतियां भी लाता है। जहां आने वाले नए साल में नई इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीदें रहती हैं तो वहीं साल में तरह-तरह की चुनौतियों से भी सामना करना पड़ता है। इसके लिए हर व्यक्ति पहले से स्वयं को तैयार रखता है। साल 2021 की शुरूआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल 2021 को कुंभ में प्रवेश करेंगे पुनः 14 सितंबर 2021 को वक्री होकर मकर में आएंगे। इसके बाद 21 नवम्बर 2021 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृष राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेगा। यहां प्रस्तुत भविष्यवाणी चन्द्र राशि, लग्न तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर है। आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी राशि... आचार्य राजेश कुमार

मेष राशि

करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी। ये साल मुख्य रूप से आपके करियर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस साल आपको अपने करियर में कर्मफल दाता शनि देव की अपार कृपा प्राप्त होगी। जो आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन्न-चित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा रह सकता है ।

वृषभ राशि

यह साल आपके लिए नई सफलताएं और उपलब्धियों वाला रहेगा। 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के भी योग आपके लिए बना रहा है। इस वर्ष आपको अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही अपॉर्च्युनिटी हासिल करनी होगी तभी आप एक अच्छे वर्ष का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करने का कार्य करेंगे।

मिथुन राशि

इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिथुन राशि वालों के बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। प्रत्येक कार्य में देरी और विघ्न की स्थिति बनेगी, बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते आर्थिक हानि होने की भी संभावना अधिक है। यह समय आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने का है।

कर्क राशि

ये साल करियर की दृष्टि से अच्छे परिणामों को लेकर आएगा। क्योंकि जहां साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर तरक्की दिलाएंगे। वहीं, दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि और बृहस्पति की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम दिलाएगी। आर्थिक जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत बेहतर साबित होगी। मार्च से मई के दौरान स्थितियां काफी बदल जाएंगी। इस समय आपको अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं।

सिंह राशि

आर्थिक दृष्टि से ये साल ठीक-ठाक रहने वाला है। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। छोटी-छोटी सफलताओं के साथ आप बड़ी सफलता की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहां आपको बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है पढ़ाई में किसी भी तरह का शार्ट-कट ना लें अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कन्या राशि

यह वर्ष आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। जहां साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इस वर्ष करियर में आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। नई-नई योजनाएं आपके जहन में आ सकती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को हानि होने की आशंका अधिक है। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत और साल का अंत सबसे बेहतर रहने वाले हैं।

तुला राशि

वर्ष 2021 आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। जहां आपको इस वर्ष कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी इस समय आएंगे। अगर करियर की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जून से जुलाई के बीच के मध्य समय में मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा जिसके चलते आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफी लाभ होगा। आपको कार्यक्षेत्र में भरपूर सफलता मिलने से उन्नति की प्राप्ति होगी।

वृश्चिक राशि

यह साल आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा। हालांकि, आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। पुराने समय से चली आ रही किसी बीमारी से आप उबर जाएंगे। आपको जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर काफी मेहनत करनी होगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष काफी अनुकूल रहेगा और आप में से कुछ लोगों को विवाह की शहनाइयां सुनने का मौका मिलेगा और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल होंगे। हालांकि विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है।

धनु राशि

यह साल आपके करियर की दृष्टि से अधिक बेहतर रहेगा। सहकर्मियों की मदद से अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उन्हें बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला-जुला रहेगा, स्वास्थ्य जीवन पिछले वर्ष के अनुसार काफी बेहतर होगा। हालांकि शनि देव आपकी परीक्षा लेते हुए बीच-बीच में आपको कुछ कष्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु की युति आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी, जिस कारण आप अपने करियर में बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जाएंगे व्यापारियों के लिए भी यह साल विशेष शुभ रहने वाला है। आर्थिक जीवन में शुरुआती कुछ महीनों में परेशानी आएंगी, लेकिन वर्ष के मध्य भाग में धन की आवाजाही आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ करने के कई अवसर देंगे।

कुंभ राशि

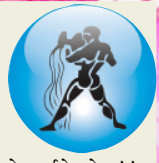

इस साल कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस साल आपकी नौकरी में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक जीवन में अचानक से खर्च में वृद्धि नजर आएगी, जिसके चलते कुछ समय के लिए आर्थिक तंगी महसूस होगी। अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी। इसलिए मेहनत पर विश्वास करना अधिक उचित रहेगा। विद्यार्थियों को इस साल अधिक मेहनत करनी होगी।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस वर्ष करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। आप इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की जरूरत होगी। तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की होगी

SBI ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू करने वाला है। ये 50 हजार रुपये से अधिक चेक पेमेंट के नियमों पर लागू होगा। एसबीआई ग्राहकों को 1 जनवरी से 50 हजार रुपये से अधिक की कीमत वाले चेक जारी करते समय अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अमाउंट, चेक डेट आदि की जानकारी चेक पेमेंट के लिए देनी होगी। एसबीआई पॉजिटिव पे सिस्टम ग्राहकों का विकल्प दे रहा है और इस बारे में कोई भी सवाल होने पर आप बैंक ब्रांच को संपर्क कर सकते हैं।

लागू होगा नया सिस्टम

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकारी दी जाएगी।

नए नियम के तहत पांच अहम बदलाव

1. पॉजिटिव पे सिस्टम बड़े भुगतान वाले चेक के विवरणों को फिर से जांचने की प्रक्रिया है।

2. बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाताधारकों के लिए नया नियम लागू करेंगे। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाताधारक करेगा। बैंक पांच लाख रुपये और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर सकते हैं।

3. नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की जानकारी एसएमएस, मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से दे सकता है। चेक का भुगतान से पहले इन जानकारियों की दोबारा जांच की जाएगी।

4. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) पॉजिटिव पे सिस्टम को विकसित कर इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा।

5. केवल वे चेक जो नए नियम के तहत आएंगे वे सीटीएस ग्रिड विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे। सभी बैंकों को चेक क्लियर या संग्रह में नए नियम को लागू करना होगा।

ग्राहकों को जागरूक करना जरूरी

आरबीआई ने सभी बैंकों को1 जनवरी से पहले नए चेक के नियम से अवगत कराने के लिए जागरूक करने को कहा है। इसके लिए ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजने को कहा गया है। साथ ही बैंक शखा में डिस्पले लगाकर नए नियम के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान भी इस नई जानकारी से ग्राहकों को अवगत कराने को कहा गया है।

एमसीएक्स ने प्राकृतिक रबड़ में वायदा कारोबार शुरू किया

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रमुख जिंस एक्सचेंज एमसीएक्स ने सोमवार को प्राकृतिक रबड़ में वायदा कारोबार शुरू कर दिया। इसमें वर्ष 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में समाप्त होने वाले चार अनुबंधों को कारोबार के लिए सामने रखा गया है। छोटे-मध्यम आकार के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं तथा बड़े उद्योग घरानों सहित हाजिर कारोबारियों की मजबूत मांग के बाद रबड़ वायदा की शुरुआत की गई। एमसीएक्स के सीईओ और प्रबंध निदेशक पीएस रेड्डी ने एक बयान में कहा, ''उत्पादन और आयात के मामले में भारत में प्राकृतिक रबड़ के विशाल बाजार और इसकी वैश्विक मूल्य संबद्धता और उतार चढ़ाव को देखते हुए, एक्सचेंज में रबड़ वायदा की शुरुआत, मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए रबड़ उद्योग के अंशधारकों के लिए महत्व रखता है।'' एमसीएक्स में रबड़ वायदा, सप्ताह के कामकाज वाले दिनों में सुबह नौ से शाम पांच बजे तक व्यापार के लिए उपलब्ध होगा।

दुपहिया उद्योग को चौथी तिमाही में वृद्धि की उम्मीद, पर किसान आंदोलन, बजट को लेकर सतर्कः एचएमएसआई

नयी दिल्ली। एजेंसी

दुपहिया वाहन उद्योग को वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में एक अंकीय वृद्धि की उम्मीद है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हालांकि, कहा कि किसान आंदोलन और आगामी बजट को लेकर निकट भविष्य में कुछ अनिश्चितताएं भी हैं। उद्योग को उम्मीद है कि पिछले साल के कम आधार प्रभाव और इस साल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खुलने के साथ ही छात्रों के लिये दुपहिया वाहनों की मांग बढ़ेगी। एचएमएसआई के निदेशक (बिक्री और विपणन) यदविंदर सिंह गुलेरिया ने न्यूज एजेंसी को बताया, ''हमें बीएस-4 से बीएस-6 पर जाना था, जिसके कारण वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में बिक्री कम हुई और वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए उसका आधार प्रभाव रहा रहा। इसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में एक अंक वृद्धि होगी।'' वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि कंपनी को जनवरी-मार्च के दौरान दोपहिया उद्योग के लिए कैसी वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही से बहुत अधिक उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि किसान आंदोलन और बजट को लेकर कुछ अनिश्चितताएं हैं। इन दोनों बातों पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन से ग्रामीण बिक्री पर असर पड़ेगा, जहां मोटरसाइकिलों को मुख्य रूप से बेचा जाता है, जबकि उद्योग इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कैसा बजट पेश किया जाएगा। गुलेरिया ने आगे कहा कि कर संग्रह को लेकर सरकार पर बहुत दबाव है और ऐसे में बजट को लेकर उद्योग सतर्क है।

भारत ने यूरोपीय देशों को चावल निर्यात के लिये प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता को जुलाई तक टाला

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत ने मंगलवार को बासमती और गैर-बासमती चावल, यूरोपीय देशों को निर्यात करने के लिए एक सरकारी एजेंसी से निरीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को एक जुलाई, 2021 तक के लिए टाल दिया है। पहले यह तारीख अगले साल एक जनवरी थी। निदेशालय ने कहा कि 10 अगस्त की एक अधिसूचना ''इस हद तक संशोधित की गई है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य यूरोपीय देशों - आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को चावल (बासमती और गैर-बासमती) का निर्यात करने के लिए ही केवल ईआईए / ईआईसी से निरीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।'' निदेशालय ने कहा कि शेष यूरोपीय देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को छोड़कर) को निर्यात के लिए, एक जुलाई 2021 से निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) या निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) से निरीक्षण प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता होगी। भारत, दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक देश है और यह यूरोपीय संघ को लगभग तीन लाख टन बासमती चावल का निर्यात करता है। निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है, जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस परिषद के तहत आने वाली निर्यात निरीक्षण एजेंसियां (ईआईए) मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में 'सबसे अधिक लचीली' साबित हो सकती हैः संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के प्रकोप के बाद दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के उप-भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था ''सबसे अधिक लचीली'' साबित हो सकती है। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया कि कोविड-19 के बाद कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि और बड़े बाजार के कारण भारत निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना रहेगा। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) द्वारा जारी 'एशिया और प्रशांत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझान और परिदृश्य 2020/2021' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में एफडीआई प्रवाह की आवक दो प्रतिशत घटी है और यह 2018 के 67 अरब डॉलर के मुकाबले 2019 में 66 अरब डॉलर रही। हालांकि, इस दौरान भारत में एफडीआई आवक सबसे अधिक रही, और इस उप-क्षेत्र में कुल

एफडीआई में उसकी 77 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। इस दौरान भारत में 51 अरब डॉलर बतौर एफडीआई आए, जो इससे पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रवाह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और निर्माण क्षेत्र के हिस्से आया। आईसीटी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमईएन) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं से संपन्न स्थानीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश कर रहे हैं और खासतौर से ई-कॉमर्स में काफी अंतरराष्ट्रीय निवेश आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया से एफडीआई बहिर्गमन लगातार चौथे वर्ष बढ़ा और ये 2018 के 14.8 अरब अमरीकी डालर से बढ़कर 2019 में 15.1 अरब अमरीकी डालर हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि लंबी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक लचीली साबित हो सकती है और भले ही महामारी के बाद आर्थिक विकास दर कम हो जाए, लेकिन बड़े बाजार की मांग के चलते यहां निवेश आता रहेगा। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2025 तक आईटी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, डिजिटल संचार सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुख्य डिजिटल क्षेत्र का आकार दोगुना हो सकता है।

अगले साल से सभी बीमा कंपनियों को प्रीमियम का देना होगा ब्योरा

ग्राहकों को होगा फायदा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

स्वास्थ बीमा खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब स्वास्थ्य बीमा खरीदने से पहले आपको बीम कंपनी प्रीमियम की गणना का अधार और उसके एवज में मिलने वाले लाभ जानकारी उपलब्ध कराएगी। ऐसा बीमा नियामक इरडा के निर्देश पर होने जा रहा है। बीमा नियामक इरडा ने 1 अप्रैल, 2021 से पहले सभी स्वास्थ्य बीमा देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह पॉलिसी के लाभ/प्रीमियम की गणना का खुलास करें। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और फैमिली फ्लोटर दोनों पर लागू होगा।

दिल्ली स्थित ऑनलाइ बीमा ब्रोकिंग फर्म सिक्योरनाऊ.इन के निदेशक चंदन डी. एस. डांग ने बताया कि हाल के दिनों में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ऐड-ऑन, एनआईएल क्लेम बोनस इत्यादि कई लाभ के कारण काफी जटिल हो गई है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि बीमा धारक आसानी से पॉलिसी की कीमत और उसमें मिलने वाले लाभ को समझें। इरडा के इस पहल से यह भी होगा कि जो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी खरीदने जा रहा है उसे पता होगा कि उसके परिवार में किसे कितना का कवर मिला है।

पॉलिसी को समझना जटिल हो गया था

पॉलिसी बाजार.कॉम के प्रमुख (स्वास्थ्य बीमा) अमित छाबड़ा ने बताया कि मौजूदा समय में कोई व्यक्ति अकेले के लिए या पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदता है। उसे पॉलिसी में मिलने वाला कवर को समझना मुश्किल हो गया है। इरडा के इस निर्देश के बाद बीमा कंपनियां प्रीमियम से लेकर कवर की राशि और लाभ का खुलासा करेगी। इससे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदना आसान होगा।

बीमा धारक को कैसे फायदा मिलेगा?

बीमा कंपनियों को व्यक्तिगत और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की पेशकश में सांकेतिक उम्र / बीमा राशि के साथ लाभ का ब्योरा प्रदान करना होगा। इसके अलावा, उत्पाद निर्माण के आधार पर और कवर किए जाने वाले परिवार के सदस्यों के योग्य मापदंडों के अनुसार, सांकेतिक आयु का चयन भी करना होगा। इसमें 20 साल या कम, 21 से 30 साल, 31 से 40 साल, 41 से 50 साल, 51 से 60 साल, 61 से 65 साल और 66 या उससे अधिक के आधार पर चयन करना होगा। इस पहल से बीमा खरीदने वाले को प्रीमियम चुकाने के एवज में मिलने वाले लाभ का पता होगा।

खरीदने से पहले लाभ का पता होगा

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि इरडा के इस पहल से स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को पता होगा कि वह जो प्रीमियम चुकाने जा रहा है उसमें उसे क्या लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह कदम स्वास्थ्य बीमा खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा।

कई गुना बढ़ा दिए थे प्रीमियम

माना जा रहा है कि बीमा नियामक इरडा ने हाल के दिनों में

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कई गुना बढ़ोतरी को देखते हुए उठाया है। गौरतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूजंस के मानकीकरण पर अनिवार्य किए गए नियमों के 1 अक्तूबर 2020 से प्रभावी होने के बाद से ही कई बीमा धारकों ने शिकायत की है कि उनके प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी हो गई है। बीमा धारकों ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम 40-70 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इरडा ने कहा है कि नियम में बदलाव की वजह से प्रीमियम में बदलाव पांच फीसदी से ज्यादा नहीं है। नियमाक ने कहा था कि 30 सितंबर 2020 तक कुल 388 उत्पादों में से केवल 55 में प्रीमियमों में 5 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है।

नए साल में बदल जाएंगे म्युचुअल फंड में निवेश से जुड़े ये 5 नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

बाजार नियामक सेबी नए साल में म्युचुअल फंड के नियमों में बदलाव करने जा रहा हैं। म्युचुअल फंड्स को निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव एक जनवरी से और कुछ उसके बाद लागू होंगे। अगर आप साल 2021 में म्युचुअल फंड्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको नियमों में होने वाले इन बदलावों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये बदलाव कौन-कौनसे हैं।

नया रिस्कोमीटर टूल

बाजार नियामक सेबी निवेशकों को निवेश के पहले रिस्क का अंदाजा लगाने के लिए एक रिस्कोमीटर टूल की सुविधा देता है। अब इस टूल में 1 जनवरी 2021 से 'बहुत अधिक जोखिम' की कैटेगरी भी जोड़ दी जाएगी, जिससे निवेशक उत्पाद के बारे में सटीक अंदाजा लगा सकें। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। हर महीने इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। एक जनवरी से सभी योजनाओं पर अलग से जोखिम की श्रेणी दर्शायी जाएगी और फंड हाउस को योजना के रिस्क प्रोफाइल में बदलाव होने पर निवेशकों को सूचित करना होगा।

मल्टी-कैप इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं के लिए पोर्टफोलियो आवंटन

सितंबर महीने में सेबी ने मल्टी-कैप इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं के लिए पोर्टफोलियो आवंटन में कुछ बदलाव किये थे। अब बदले हुए नियमों के अनुसार, किसी मल्टी-कैप म्युचुअल फंड स्कीम को 65 फीसद के स्थान पर कम से कम 75 फीसद इक्विटी में निवेश करना होगा। मल्टी कैप इक्विटी म्युचुअल फंड्स स्कीम्स में कम से कम 25-25 फीसद हिस्सा लार्ज कैप, मिडकैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना होगा। वर्तमान में मल्टी-कैप फंड कैटेगरी में कोई आवंटन से जुड़ा प्रतिबंध नहीं है।

NAV गणना में बदलाव

एक जनवरी 2021 से म्युचुअल फंड निवेशकों को नेट एसेट वैल्यू यानी परचेज NAV एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास पैसे पहुंच जाने के बाद मिलेगा, चाहे निवेश का आकार कितना भी बड़ा क्यों न हो। यह लिक्विड और ओवरनाइट म्युचुअल फंड स्कीम्स पर लागू नहीं होगा। अभी तक दिन का 2 लाख तक परचेज NAV, AMC के पास पैसे पहुंचने से पहले मिल जाता था।

सिक्युरिटीज का इंटर-स्कीम ट्रांसफर

एक जनवरी, 2021 से क्लोज इंडेड फंड्स का इंटर-स्कीम ट्रांसफर निवेशकों को स्कीम की यूनिट एलॉट होने के केवल तीन कारोबारी दिनों के अंदर करना होगा। तीन कारोबारी दिन के बाद ऐसे ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।

बदलेगा डिविडेंड ऑप्शन का नाम

एक अप्रैल, 2021 से म्युचुअल फंड्स स्कीम्स के सभी डिविडेंड ऑप्शंस का नाम बदलकर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉअल ऑप्शन (income distribution cum capital withdrawal) हो जाएगा।

मार्च तक बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर 10.1-10.6 प्रतिशत होगा : इक्रा

मुंबई। एजेंसी

बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) मार्च, 2021 तक बढ़कर 10.1 से 10.6 पर पहुंच जाएंगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह अनुमान जताया। इक्रा ने कहा कि इस दौरान बैंकों का शुद्ध एनपीए 3.1 से 3.2 प्रतिशत रहेगा। हालांकि, रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मार्च, 2022 तक शुद्ध एनपीए घटकर 2.4-2.6 प्रतिशत रह जाएगा। इक्रा की रिपोर्ट में कहा गया है, ''ऋण की किस्त के भुगतान पर रोक अब समाप्त हो चुकी है। संपत्ति वर्गीकरण पर अभी उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार है। निकट भविष्य में बैंकों का सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए बढ़कर क्रमशः 10.1-10.6 प्रतिशत और 3.1-3.2 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। सितंबर, 2020 तक यह क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत था।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में शुद्ध एनपीए और कर्ज के लिए प्रावधान निचले स्तर पर रहेगा, क्योंकि बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में मजबूत संग्रह हुआ है।

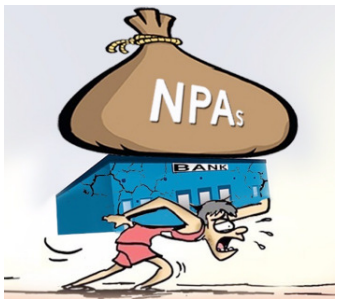

ज्यादातर बैंकों का संग्रह 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। इक्रा ने कहा कि ऋण पुनर्गठन के आग्रह पूर्व में लगाए गए अनुमान से कहीं कम है। इसकी वजह अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार और सरकार की आपात ऋण गारंटी योजना है। एजेंसी ने अपने ऋण पुनर्गठन अनुमान को घटाकर 2.5 से 4.5 प्रतिशत कर दिया है। पहले उसने इसके 5 से 8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इक्रा के क्षेत्र प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र रेटिंग) अनिल गुप्ता ने कहा, ''सतत संग्रह और पुनर्गठन निचले स्तर पर रहने से संपत्ति की गुणवत्ता और सुधरेगी। शुद्ध एनपीए मार्च, 2022 तक घटकर 2.4 से 2.6 प्रतिशत रह जाएगा। इससे ऋण के लिए प्रावधान घटेगा और वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा।'' रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कर्ज को लेकर प्रावधान 2021-22 में घटकर 1.8 से 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में इसके 2.2 से 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2019-20 में यह 3.1 प्रतिशत रहा था।

सरकार ने एथनॉल डिस्टिलरीज के लिए 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता को मंजूरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथनॉल का उत्पादन करने वाली नयी डिस्टिलरीज के लिए 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। इस एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधान ने कहा कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को 2030 तक 1,000 करोड़ लीटर एथनॉल की जरूरत होगी। अभी देश की एथनॉल उत्पादन क्षमता 684 करोड़ लीटर की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथनॉल आसवन क्षमता के विस्तार के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जौ, मक्का जैसे मोटे अनाज, गन्ने और चुकंदर से पहली पीढ़ी के एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।